



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 94/2020
GST Circular No. 50/2020

2016/AC-11/01/06/CRIS

17th December, 2020

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Amendment to turnover threshold for e-invoicing under GST

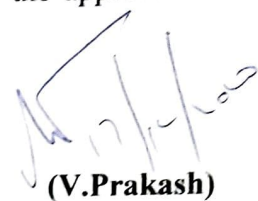
Ref: Railway Board's letter dated 8th October 2020 (RBA No. 78/2020)

Railway Board vide letter *ibid.* had *inter-alia* highlighted the process for procurements of supplies with effect from 1st October 2020. It was stipulated therein that registered persons (suppliers to Railways) having aggregate turnover more than INR 500 crores in a financial year, is liable to issue e-Invoice. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), vide Notification No.88/2020-Central Tax dated 10th November 2020, has now **increased the applicability of e-invoice to encompass, with effect from 1st January 2021, registered persons having aggregate turnover exceeding INR 100 crores in a financial year.**

Thus, pursuant to such Notification, **with effect from 1st January 2021**, all suppliers of Indian Railways (other than certain exempted categories) having aggregate turnover more than INR 100 crores in any of the preceding Financial Years i.e. FY 2017-18, FY 2018-19 or FY 2019-20 shall comply with e-invoicing provisions and thus, any e-invoice issued by such suppliers shall mandatorily have Quick Response (QR) Code encompassing the requisite particulars. It is mentioned that all the vendor's invoices dated 1.1.2021 onward shall be governed by the threshold limit of Rs. 100 crore for issuance of e-Invoice. **All invoices dated prior to 1.1.2021**, eventhough received in Railways after 1.1.2021, shall be governed by the threshold limit of Rs. 500 crore as brought out in RBA 78/2020. In this respect, the mechanism followed till date for existing suppliers of e-invoicing such as obtaining declarations, mapping in IREPS/IPAS etc. shall also be followed for aforementioned suppliers with effect from 1st January 2021. CRIS is being requested to validate the existing applications such as IPAS, IRePS, etc to give effect to the above notification.

P.T.O

All the Zonal Railways/Production Units may kindly see the above changes in GST Law and ensure its compliance in consultation with GST Consultants. This issues with the approval of competent authority.



(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS, GM/IRePS, CRIS
6. **Chief Executive Officer**, Ministry of Commerce and Industry, Government e-Marketplace, 2nd Floor, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, New Delhi 110 001. [with a request to give effect to the above in GeM portal as requested in Ministry of Railway's letter dated 27.11.2020, to ensure GST compliance.



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 94/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 50/2020

2016/एसी-II/01/06/क्रिस

17 दिसंबर, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- जीएसटी के अंतर्गत ई-बीजकन (ई- इनवॉइसिंग) के लिए टर्नओवर सीमा में संशोधन

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 78/2020)

रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्वोक्त पत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से आपूर्तियों की खरीद की प्रक्रिया को उजागर किया है। इसमें यह अनुबंधित किया गया था कि एक वित्त वर्ष में भारतीय रुपयों में 500 करोड़ रुपये से अधिक की कुल टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति (रेलों के आपूर्तिकर्ता), ई-बीजक जारी करने के लिए दायी होंगे। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. 88/2020-केन्द्रीय कर के तहत अब 1 जनवरी, 2021 से एक वित्त वर्ष में भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से अधिक के कुल टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों को शामिल करने के लिए ई-बीजक लागू करने की प्रयोज्यता को बढ़ा दिया है।

अतः, ऐसी अधिसूचना के अनुसार, पिछले किसी वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19 अथवा वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय रुपयों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कुल टर्नओवर वाले भारतीय रेल के सभी आपूर्तिकर्ताओं (कुछ विशेष कोटियों के अलावा) को 1 जनवरी, 2021 से ई-बीजक के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे और इसलिए ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी ई-बीजक में अनिवार्य रूप से क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) कोड, जिसमें अपेक्षित विवरण शामिल हो, होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 1.1.2021 से सभी वेंडरों के बीजक, ई-बीजक को जारी करने के लिए 100 करोड़ रुपये की सीमा द्वारा शासित होंगे। 1.1.2021 से पहले के सभी बीजक, भले ही वे रेलों को 1.1.2021 के बाद प्राप्त हुए हों, 500

करोड़ रुपये की सीमा द्वारा शासित होंगे जैसाकि आरबीए 78/2020 में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, ई-बीजकन जैसे घोषणापत्र प्राप्त करना, आईआरईपीएस/आईपीएस आदि में मैपिंग करने हेतु मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के लिए अब तक लागू मैकेनिज़्म, 1 अप्रैल, 2021 से पूर्वकथित आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी लागू होगा। उक्त अधिसूचना को लागू करने हेतु क्रिस से मौजूदा एप्लीकेशनों जैसे आईपीएस, आईआरईपीएस आदि को मान्य करने के लिए अनुरोध किया गया है।

कृपया सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां जीएसटी कानून में किए गए उपर्युक्त परिवर्तनों को देखें और जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड